POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 अगस्त, 2025 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जमीनी स्तर पर नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खास योजना बनाई है। इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के 5000 गांवों को चुना गया है।

प्रदेश में 24 जून से 9 जुलाई तक इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अंत्योदय संबल पखवाड़ा एवं शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं उनसे ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए कैम्प लगाए गए। इस योजना में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी सुविधाओं के विकास को खास महत्व दिया गया है।

कई कार्यक्रमों में स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार गरीबों, किसानों, मजदूर वर्ग और युवा वर्ग की हितैषी है। सरकार का लक्ष्य गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, जैसे कई क्षेत्रों में तेज गति से काम कर रही है।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए बीते वर्षों में अनेक ठोस व तकनीकी रूप से सक्षम योजनाएं लागू की गई हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। जरूरी यह भी है कि सरकार में निरंतर सुधार की प्रक्रिया धरातल पर क्रियान्वित होती दिखाई दे। प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार आए, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो।

'लावारिस' वक्फ संपत्ति से विधवा व अनाथ बच्चों को मिलेगा पैसा

केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे वक्फ संपत्तियों की आय से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के साथ अनाथ बच्चों को सीधे खाते में रकम पहुंचाकर संबल देने का रास्ता खुल गया है।

इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके क्या होंगे, ऑडिट का संचालन और खातों का रखरखाव किस तरह किया जाएगा, इन्हें लेकर भी नियम बना दिए गए हैं। दरअसल वक्फ संशोधन कानून पर सियासी और कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन कानून लागू करने के लिए जरूरी नियम जारी करने के बाद यह अमल में आएगा। नियमों के तहत प्रत्येक वक्फ व संपत्ति को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे सभी राज्यों में उनकी ट्रैकिंग और निगरानी संभव होगी। संशोधित वक्फ कानून 2025 के लागू होने, यानी 8 अप्रेल के बाद बनाए गए सभी नए वक्फों को उनकी स्थापना के 3 महीने के अंदर-अंदर वक्फ बोर्ड के समक्ष पंजीकरण कराना जरूरी है।

दवाई के पत्ते (स्ट्रीप) में टेबलेट नहीं, विक्रेता व निर्माता पर हर्जाना

किशनपोल निवासी रितू काला व देवांग काला ने जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय में मैसर्स सात्विक मेडिकल स्टोर एवं फार्मा कंपनी मै. लोगोस फार्मा व अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने परिवाद में कहा कि उनकी स्किन पर चकत्ते होने पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के परामर्श के बाद 3,159 रुपए के बिल का भुगतान किया। उन्हें दिए गए दवाई के पत्ते में कुछ दवा की टेबलेट नहीं निकली। वहीं दवाई के पत्ते व बिल में टेबलेट की एक्सपायर डेट भी अलग-अलग अंकित की गई। इस गफलत के चलते उन्होंने दवाओं का सेवन भी नहीं किया।

मामले की सुनवाई पर जिला उपभोक्ता आयोग ने मरीज को दी गई दवाई के पत्ते में टेबलेट नहीं निकलने और इनसे पूरी दवाई की राशि लेने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। आयोग ने विपक्षी मै. सात्विक मेडिकल स्टोर व फार्मा कंपनी मै. लोगोस फार्मा सहित अन्य पर 21 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षियों को निर्देश दिया है कि वे दवा के पत्ते में नहीं निकली टेबलेट्स की राशि 110 रुपए व 114.40 रुपए उन्हें परिवाद दायर होने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करें।

प्रदेश के गांव बनेंगे गरीबी मुक्त

प्रदेश में गांवों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' शुरू की है। पहले चरण में राज्य के 5002 गांवों में कुल 30,631 बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया गया है। इन गांवों के चयनित परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

इनमें 22,400 ऐसे परिवार हैं, जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इनके बैंक खातों में सम्मान स्वरूप 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही इन परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप 'आत्मनिर्भर परिवार कार्ड' भी प्रदान किए जाएंगे। योजना में सरकार की अन्य योजनाओं का भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि गांवों का समग्र विकास हो सके।

बच्चे नहीं हुए तो वृक्षों को माना बेटा

कर्नाटक के हासन की 113 साल की पद्म श्री सालुमारदा थिमाक्का पेड़ों की मां के नाम से चर्चित हैं। थिमाक्का ने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों को पालने-पोसने में ही खपा दी। उनके बच्चे नहीं हुए तो वह पेड़ों को बेटा मानने लगी।

वह अब तक 8000 से भी अधिक पेड़ लगा चुकी है और बच्चों की तरह उन्हें पाल-पोषकर बड़ा भी किया है। उनका सबसे उल्लेखनीय काम करीब 400 बरगद के पेड़ लगाना रहा। ये पेड़ हुल्लूर और कुदूर के बीच हाइवे पर करीब चार किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। धरती की हरियाली बढ़ाने वाली इस दादी का हर शख्स शुक्रगुजार है। हाल ही में एक फिल्मकार ने भी उन पर बायोपिक का ऐलान किया है। हालांकि, थिमाक्का ने इस पर ऐतराज जताया है।

खराब हो रही है उपजाऊ भूमि की सेहत

रासायनिक खाद व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से प्रदेश में उपजाऊ जमीन की सेहत खराब हो रही है। कई जिलों के खेत पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से जारी मिट्टी के नमूनों की जांच रिपोर्ट से यह सामने आया है।

कई जिलों की मिट्टी में नाइट्रोजन निम्न स्तर पर, तो फास्फोरस, पोटाश, जिंक, लोहा व कॉपर जैसे पोषक व सूक्ष्म खनिज तत्वों की कमी पाई गई है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या में गिरावट आई है और भूमि की जलधारण क्षमता भी घटी है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को खेतों में पोषक तत्व व उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक, जैविक व हरी खाद और वर्मी कम्पोस्ट अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में राज्य के 41 जिलों में कुल 5.39 लाख मिट्टी के नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य है।

ग्राम पंचायतों में हो रोजाना सफाई

अब प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में रोजाना सफाई होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर सफाई की स्थिति की रिपोर्ट अपडेट करनी होगी, ताकि सफाई व्यवस्था की सही स्थिति का पता चल सके।

पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए बीएसआर रेट जारी करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। जिन ग्राम पंचायतों में बीएसआर रेट से टेंडर नहीं हुए हैं, वहां भी सफाई नहीं रुकनी चाहिए। वहां सफाई के अन्य विकल्पों का चयन करें। अभियान चलाकर पॉलीथीन इकट्ठा कर रिसाइकल यूनिट तक पहुंचाएं। शौचालय कार्यशील हों और हर व्यक्ति शौचालय का उपयोग करें।

पर्यटन को मिले उद्योग का दर्जा

नीति आयोग में विशेष सलाहकार डॉ. ललित के. पंवार ने सुझाव दिया है कि राजस्थान की तरह दूसरे राज्यों में भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इसके लिए पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड बनाया जाए तो देश में पर्यटन विकास की गति को और तेजी से बढ़ाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन को जन उद्योग बनाने पर जोर दिया जाए। पर्यटन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधि है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है, जो एक साथ 11 लोगों को रोजगार देता है।

कृषि ऋण घटा, विकास दर हुई कम

राजस्थान में करीब 60 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन बैंकों से दिए जा रहे कृषि ऋण की वृद्धि दर धीमी हो रही है। वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र की ऋण वृद्धि दर 13 प्रतिशत थी, जो 2025 में घटकर 9 प्रतिशत रह गई है।

इस वजह से वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की जीडीपी में कृषि विकास दर 2.5 फीसदी से भी कम रही। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंक केवल फसल संबंधी ऋण पर जोर दे रहे हैं, इससे कृषि ऋण की वृद्धि घट रही है। उनका कहना है कि बैंकों को कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी पशुपालन व फूड प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों के लिए किसानों को ज्यादा ऋण देने होंगे।

पंचायतों में बन रहे हैं खेल मैदान

प्रदेश की हर पंचायत में खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं। अब तक 9352 पंचायतों में खेल मैदान बन कर तैयार हो गए हैं तथा 4272 पंचायतों में काम तेजी से चल रहा है। पिछले दो साल में ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनने की रफ्तार पिछले 9 साल के मुकाबले चार गुना बढ़ी है।

ज्यादातर खेल मैदान स्कूलों में ही बने हैं। केंद्र सरकार के 'फिट इंडिया' की तर्ज पर 'फिट राजस्थान' को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों में विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि के साथ नैट्स आदि खेल सामग्री भी भेजी जा रही है। इससे गांव का युवा नियमित रूप से खेलों में भाग लेगा और शारीरिक रूप से सशक्त बनेगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव से खिलाड़ी निकले और राज्य व देश का नाम विश्व में रोशन करें।

अयोध्या में बने मंदिर से जगी चेतना

मध्यप्रदेश के गोहलारी गांव में चंदा जमा कर राम मंदिर क्या बना, पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। गांव की एक बुजुर्ग महिला नत्थी बाई ने 14 साल पहले मंदिर के लिए जमीन दी थी। लेकिन वर्षों भूमि खाली पड़ी रही। अयोध्या में बने मंदिर से गांव में ऐसी चेतना जगी कि गांव में श्रीराम मंदिर तो बना ही साथ ही 'राम भक्त मंदिर बैंक' भी बन गया।

ग्रामीणों ने चंदा कर उक्त जमीन पर श्रीराम मंदिर बनाया। बाकी बचे तीन लाख रुपए से 'राम भक्त मंदिर बैंक' की शुरुआत की। इस बैंक से गांव के जरूरतमंद को 25 हजार रुपए तक का ऋण महज दो फीसदी ब्याज पर दिया जाता है। इस अनूठे बैंक से अब तक गांव के 32 किसानों ने फसल बोवनी और बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण लिया और समय पर ब्याज सहित वापस जमा कराया। वे फसल कटने पर एक से लेकर पांच किलो तक अनाज मंदिर में जमा कराते हैं। इससे प्रसादी की व्यवस्था होती है।

प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की बहार

केंद्र सरकार ने देश के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की बहार लाने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की एंप्लायमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआइ) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दो साल में 3.5 करोड़ से भी अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केबिनेट ने विनिर्माण क्षेत्र पर खास जोर देते हुए सभी प्रमुख सेक्टर में रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस योजना को हरी झंडी दी है। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15 हजार रुपए तक केंद्र सरकार दो किस्तों में अपनी तरफ से देगी। साथ ही नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि देने का भी प्रावधान है।

भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी में अग्रणी

डिजिटल इंडिया के दस साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत देश को डिजिटल रूप से सशक्त व तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी।

उन्होंने कहा यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण एवं दुनिया का भरोसेमंद इनोवेशन पार्टनर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अब डिजिटल प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बन गया है। 'देश डिजिटल शासन' से 'ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप' की ओर बढ़ेगा। अब इंडिया-फर्स्ट से इंडिया फॉर-द-वर्ल्ड की ओर रुख करेगा।

हर जिले की होगी पांच पहचान

प्रदेश के हर जिले की अपनी पहचान होगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन व खेल से जुड़े पंच गौरव तय कर उनके विकास का प्लान तैयार होगा। इसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट भी दिया जाएगा।

जिलों में बजट की उपलब्धता व आवश्यकता की जानकारी जुटाकर प्लान को जमीन पर उतारने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस प्रयास को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को 'पंच गौरव' नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से हर जिले को नई सांस्कृतिक व आर्थिक पहचान दी जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं।

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा

सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर जारी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (एनआईएफ) प्रगति रिपोर्ट 2025 ने टिकाऊ विकास के लिए भारत की तस्वीर साफ कर दी है।

रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले एक दशक में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां दर्ज की है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य व्यय जैसे क्षेत्रों में अब भी ठोस प्रयासों की दरकार है। स्वास्थ्य अनुसंधान पर खर्च 400 प्रतिशत बढ़ा है, पर समग्र शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय घटा है। गरीबी उन्मूलन में भारत ने अहम कदम बढ़ाए हैं। रिपोर्ट साफ संदेश देती है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए भारत को अपनी रणनीति में तेजी, समावेशिता और स्पष्टता लानी होगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर